रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3522] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 3522] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

का.आ. 4336(अ).— (अ).-केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में ताम्बा खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवा शामिल है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 में शामिल हैं, को जैसा कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1015(अ), तारीख 7 मार्च, 2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तारीख 7 मार्च, 2018 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित की गई थी;

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तारीख 7 सितम्बर, 2018 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/11/97 - आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

S.O. 4336(E).— Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in the 'Copper Mining' industry which is covered by item **13** of the First Schedule to the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947) to be a **public utility service** for the purpose of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from 7th March, 2018 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1015(E), dated 7th March, 2018;

And whereas, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the aforesaid Act, **for a period of six months with effect from 7th September, 2018**.

[F. No. S-11017/11/97 –IR (PL)]
KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.13 15:20:57 +05'30'